

**The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE**

**Tuesday, 14 Jan, 2025**

**Edition: International Table of Contents**

<p><b>Page 01</b> <b>Syllabus : प्रारंभिक तथ्य</b></p>	<p>प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में जेड-मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया; राज्य के दर्जे पर चुप्पी साधी</p>
<p><b>Page 04</b> <b>Syllabus : GS 3 : आंतरिक सुरक्षा</b></p>	<p>भारत ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया, बाड़ लगाने के काम का बचाव किया</p>
<p><b>Page 04</b> <b>Syllabus : GS 3 : आंतरिक सुरक्षा</b></p>	<p>सेना प्रमुख ने कहा कि एलएसी पर 'कुछ हद तक' गतिरोध बना हुआ है</p>
<p><b>Page 11</b> <b>Syllabus : GS 3 : पर्यावरण</b></p>	<p>चूहा-छेद खनन क्यों अपने खतरों के बावजूद जारी है</p>
<p><b>समाचार में</b></p>	<p>मिशन मौसम</p>
<p><b>Page 08 : संपादकीय विश्लेषण:</b> <b>Syllabus : GS 1 : भारतीय समाज :</b> <b>महिलाओं से संबंधित मुद्दे</b></p>	<p>पुरुषत्व को बदलना, मर्दानगी को फिर से परिभाषित करना</p>

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में स्थित गंदेरबल के सोनमर्ग इलाके में जेड-मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया।

### सुरंग के बारे में:

- जेड-मोड़ सुरंग भारत के जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल जिले में स्थित है। यह गगनगीर से शुरू होती है और इसका अंत सोनमर्ग में होता है।
- सुरंग को गगनगीर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इस क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण स्थान हैं जो पहले भारी बर्फबारी के दौरान दुर्गम थे।
- यह जेड-मोड़ सुरंग बड़े NH1 श्रीनगर-लेह राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा है।
- इससे सोनमर्ग साल भर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा।

### जेड-मोड़ सुरंग की मुख्य विशेषताएं:

- **लंबाई और संरचना:**
  - सुरंग स्वयं 6.5 किलोमीटर लंबी है।
  - यह एक द्वि-दिशात्मक सुरंग है, जिसका अर्थ है कि वाहन दोनों दिशाओं में यात्रा कर सकते हैं।
- मुख्य सुरंग के अलावा, सुरंग के दोनों छोर तक जाने वाली 6.05 किलोमीटर की पहुंच सड़कें हैं।
- यह सुरंग समुद्र तल से लगभग 2,637 मीटर (8,652 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है।
- क्षमता और उपयोग: सुरंग को 80 किमी/घंटा की गति सीमा के साथ प्रति घंटे 1,000 वाहनों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - इसमें सुरक्षा के लिए 7.5 मीटर चौड़ी आपातकालीन निकास सुरंग शामिल है, जिसका भविष्य में रेलवे पहुंच के लिए भी संभावित उपयोग है।

## Prime Minister inaugurates Z-Morh tunnel in J&K; remains silent on Statehood

**Peerzada Ashiq**  
SONAMARG (GANDERBAL)

Prime Minister Narendra Modi, who inaugurated the strategic Z-Morh tunnel in Sonamarg area of Ganderbal on Monday, remained non-committal on the timeline of restoration of Statehood to Jammu and Kashmir. But he said the new network of roads and railway lines in the Union Territory has bridged the distance between J&K and New Delhi.

Amid freezing conditions, Mr. Modi inaugurated the state-of-the-art 6.5-kilometre tunnel built at a cost of ₹2,700 crore. The tunnel has made tourist hotspot Sonamarg a round-the-year destination. Mr. Modi said the Z-Morh tunnel and the upcoming Zojila tunnel, connecting Kashmir with Ladakh, will ease the lives of the people in Kargil and Leh.

Referring to the militant attack of October 20, 2024 that left seven workers dead at the construction site, Mr. Modi said, "I salute the dedication of workers who braved harsh weather conditions and even risked their lives to complete this project."

Describing J&K as a destination with the "distinction of having the highest rail and road bridges and rope ways", Mr. Modi said, "The engineering of the Chenab bridge has amazed people across the world. Passenger train trials were completed last week on the bridge. The projects of the Chenani-Nashri tunnel, the Udhampur-Srinagar-Baramulla railway link and the rope ways at the Shankara-



**Grand launch:** Prime Minister Narendra Modi during the inauguration of a key tunnel in J&K on Monday. IMRAN NISSAR

charya temple, Shiv Khori temple and Baltal-Amar-nath shrine are underway. In all ₹42,000-crore of connectivity projects are being executed in J&K, which include the Katra-Delhi expressway, four national highway projects, two ring roads and 14 Sonamarg-like tunnels. J&K will be the most connected region. Tourists can now reach untouched destinations."

### PM's promises

Referring to the upgraded connectivity, the Prime Minister said Viksit Bharat was only possible when all the regions of the country were well developed.

"J&K is the crown of the country and has to be beautiful and strong. I assure you Modi will walk the talk. Any hurdle in your dreams will be removed. 'Dilli ki doori' is already over now. We have to work together to fulfil dreams and have to take pledges together," the Prime Minister added.

Earlier, Mr. Abdullah, in his speech, made a case for

fulfilling the promise of restoration of Statehood. "On his previous visit to Kashmir on International Yoga Day, Prime Minister talked about three promises, which included eliminating the 'Dilli ki doori aur Dilli ki doori' [Distance of hearts and distance between Delhi-Srinagar]. People have started trusting you. You [PM Modi] have already fulfilled the promise of holding Assembly elections [in J&K], where no rigging or misuse of official machinery was reported. However, the third promise of Statehood is yet to be fulfilled," Mr. Abdullah said.

In response to Chief Minister Omar Abdullah's speech, where he referred to the Statehood demand, Mr. Modi remained silent on divulging any timeline. "When Modi makes a promise, he fulfils it. Every time has its right time. Right things will take place at the right time," he said.

**NC MOBILISES PEOPLE**

» PAGE 4

## Daily News Analysis

- न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) के साथ विकसित, यह सुरंग चुनौतीपूर्ण भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में सुरंग बनाने में अपनी दक्षता के लिए जानी जाती है।
- इंजीनियरिंग और निर्माण: सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) का उपयोग करके किया गया था, जो एक ऐसी तकनीक है जो चुनौतीपूर्ण भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में अपनी दक्षता के लिए जानी जाती है।
  - सुरंग के निर्माण में नौ साल लगे, जिसका निर्माण मई 2015 में शुरू हुआ और 2024 में पूरा होगा। निर्माण की कुल लागत 2,700 करोड़ रुपये थी।
- **सामरिक महत्व:**
  - सुरक्षा और यात्रा दक्षता: ज़ेड-मोड़ सुरंग सड़क के ज़ेड-आकार वाले हिस्से की जगह लेगी जो हिमस्खलन और भूस्खलन से ग्रस्त थी, जिससे यात्रा की सुरक्षा और दक्षता में काफी सुधार हुआ है।
  - सैन्य और नागरिक उपयोग: नागरिक उपयोग के अलावा, सुरंग क्षेत्र में सैन्य रसद के लिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
  - पर्यटन और संपर्क: ज़ेड-मोड़ सुरंग श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच यात्रा के समय को कम करने में मदद करेगी, जिससे यह क्षेत्र स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए साल भर अधिक सुलभ हो जाएगा।
  - पूरा होने पर, ज़ोजिला सुरंग (एक अन्य महत्वपूर्ण सुरंग) श्रीनगर और लद्दाख के बीच संपर्क को और बढ़ाएगी।

**Page 04 : GS 3 : Internal Security**

भारत का सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सीमा पार आवाजाही और सुरक्षा चिंताओं को रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने पर काम कर रहा है।

- ▶ हालाँकि, इस पहल पर हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आपत्ति जताई है, जो भारत के साथ पिछले सीमा समझौतों की समीक्षा कर रही है।

**भारत-बांग्लादेश सीमा**

- ▶ भारत और बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसमें से 2,216.7 किलोमीटर सीमा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, जिसमें से लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा बिना बाड़ के है।
- ▶ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं।

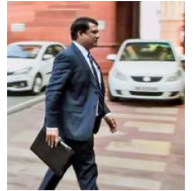
**मुख्य समझौते:**

- ▶ भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा मुद्दों को हल करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। इन समझौतों में भूमि विवादों को हल करने, सीमा सुरक्षा सहयोग में सुधार करने और सीमा के पास बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ▶ 1974 भूमि सीमा समझौता: यह समझौता भूमि विनिमय और एन्क्लेव के निपटान से संबंधित मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण था, जिसमें दोनों देशों के बीच क्षेत्रों की अदला-बदली शामिल थी। यह लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को हल करने में एक बड़ा कदम था।
  - तीन बीघा कॉरिडोर, जो बांग्लादेश को ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े तक पहुँच प्रदान करता है, भी विवाद का विषय रहा है। 1974 के समझौते के तहत, बांग्लादेश ने इस कॉरिडोर तक पहुँच के बदले में भारत को कुछ क्षेत्र सौंप दिया। हालाँकि, इस कॉरिडोर को खुला रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर विवाद पैदा हो गए हैं, खासकर नए समझौतों के साथ जो इसके पास बाड़ लगाने की अनुमति देते हैं।
- ▶ 1975 सीमा अधिकारियों के लिए संयुक्त भारत-बांग्लादेश दिशा-निर्देश: इस समझौते ने भारत और बांग्लादेश के सीमा बलों के बीच सहयोग के लिए आधार तैयार किया, सीमा के प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल स्थापित किए।
- ▶ 2011 भूमि सीमा समझौता प्रोटोकॉल: इस प्रोटोकॉल ने 1974 के समझौते के कार्यान्वयन को और विस्तृत किया, जिसमें सीमा के साथ क्षेत्रों और क्षेत्रों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- ▶ 2011 समन्वित सीमा प्रबंधन योजना: इस योजना का उद्देश्य सीमा की बेहतर सुरक्षा और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के सीमा बलों के बीच समन्वय में सुधार करना था।

**India summons Bangladesh envoy, defends fence work**

**Kallol Bhattacharjee**  
NEW DELHI

The Ministry of External Affairs (MEA) on Monday summoned the Head of Mission at the High Commission of Bangladesh to convey that fencing works on the India-Bangladesh border was being carried out in accordance with "all protocols and agreements".



Acting High Commissioner of Bangladesh to India, Md. Nural Islam, at the South Block, ANI

The conversation took place a day after Bangladesh Foreign Secretary Mohammad Jashim Uddin expressed "deep concern" to Indian High Commissioner in Dhaka Pranay Verma about the construction works by the Border Security Force (BSF) along the border.

"India reiterated its commitment to ensuring a crime-free border by effectively addressing the challenges of cross-border criminal activities, smuggling, movement of criminals and trafficking. Barbed wire fencing, border lighting, installation of technical devices and cattle fences are measures for securing the border," said the MEA in a press note, after the Acting High Commissioner of Bangladesh to India, Mohammad Nural Islam, met the Joint Secretary in-charge of Bangladesh and Myanmar division in the Ministry, B. Shyam, at South Block.

Bangladesh had conveyed to Mr. Verma that the construction of barbed wire fences on at least five locations along the Indo-Bangladesh border was "unauthorised" and had "caused tensions and disturbances along the border".

**Questions 2015 pact**

The Adviser of Home Affairs of Bangladesh, Jehangir Alam Chowdhury, had, in addition, referred to the border agreements between India and Bangladesh as "unequal", casting doubt on the Land Boun-

dary Agreement of 2015 that was concluded between Prime Minister Narendra Modi and then Prime Minister Sheikh Hasina.

Responding to Dhaka's accusations, the MEA said, "It was conveyed that with regard to security measures at the border, including fencing, India observed all protocols and agreements between the two governments and between the Border Security Force and the Border Guard Bangladesh."

The latest spat intensified after Mr. Chowdhury addressed a press conference in Dhaka on Sunday where he blamed India for carrying out constructions along the border without following due procedures. The interim government of Bangladesh has also been campaigning to reduce alleged incidents of fatal shooting by the BSF that is said to have caused civilian casualties in the recent years.

The India-Bangladesh border was considered a "settled" matter, especially after the Land Boundary Agreement was signed on June 6, 2015, for which Mr. Modi had travelled to Dhaka. However, the latest comments from Bangladesh has reopened the border debate between the two sides. Land and sharing of river waters have been a lingering issue between the two sides, and Bangladesh has been demanding its share of the Teesta's waters.

एलएसी भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव का स्थल रहा है, खासकर अप्रैल 2020 से। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उल्लेख किया कि हालांकि एलएसी पर "कुछ हद तक गतिरोध" है, लेकिन स्थिति "संवेदनशील लेकिन स्थिर" है।

## A 'degree' of stand-off prevails along the LAC, says Army chief

Gen. Dwivedi terms situation 'sensitive but stable', says Army's deployment is 'balanced and robust'; on disengagement, he says 2 rounds of verification patrolling completed; on 1971 painting row, adds new one is reaching out to newer generations

**Dinakar Peri**  
NEW DELHI

**S**tating that a "degree" of stand-off prevails along the Line of Actual Control (LAC), Army chief General Upendra Dwivedi said on Monday that he had authorised all Corps Commanders to handle issues at the ground level with respect to patrolling and grazing so that these trivial issues can be resolved at the military-level itself. He termed the situation along the LAC "sensitive but stable", and said the Army's deployment along was "balanced and robust".

"All the Corps Commanders have been empowered to go through the patrolling and grazing issues and wherever you can harmonise relations between the two sides, you should be able to do. When Special Representative talks took place a press release was given. So we are also looking at Kailash Mansarovar *yatra* to resume, some trade points to be resumed. So similarly, we are also looking at, if we can have



**Straight talk:** Army chief General Upendra Dwivedi addressing the annual press conference in New Delhi on Monday. R.V. MOORTHY

some kind of understanding please go ahead. That kind of delegation has been given to Division Commanders and Corps Commanders. They will come back to us... as far as we are concerned, from my side it is approved." General Dwivedi said in response to a question on whether an understanding had been reached with China not to block their patrols in the Yangtse area in Arunachal Pradesh.

He was addressing the annual press conference ahead of the Army Day on Wednesday.

On the recent disengagement from Depsang and Demchok in eastern Ladakh, he said two rounds of verification patrolling had been completed by both sides.

"There is nothing called as buffer zone," he said, terming them "temporary moratorium". "Where you feel that the nature or the degree of violence can be high and the fuse is short, you create some distances," he said.

"So when we carried out these negotiations over a period of time, some places were declared as a temporary moratorium. It means that both sides will remain back and will not go to the common areas because we still feel that if we meet at those places the violence level may go high."

After April 2020, the trust between the two countries has to have a new definition, he remarked and therefore, there is a requirement for

us to sit together and come to a broader understanding of how we want to calm down the situation and restore the trust.

On the situation along the Line of Control with Pakistan, the ceasefire understanding reached in February 2022 is holding on, but the terror infrastructure across remains intact and infiltrations attempts continue. "The violence level is being orchestrated by the epicentre of terrorism that is Pakistan... If the support is not forthcoming the way India is looking at it, this kind of terrorist infiltration will continue to be there," he said.

They have inducted 15,000 additional troops in 2024 and that is why the violence level has gone down and they have been able to neutralise 73 terrorists out of which 60% were from Pakistan. "The parliamentary elections and the State Assembly elections both had nearly 60% voting... All indicators show that people of J&K are shunning violence and it is being fully orchestrated by our adversary."

On the Siliguri corridor, also referred to as the Chicken's neck, and the Chinese infrastructure

near Doklam, the Army chief said that is the strongest point. "As far as Chicken's neck is concerned, I would like to put it in a different perspective. That is our strongest point, because all the forces which are there in West Bengal, in Sikkim, all the forces which are there in North-east, from all the three sides our forces can congregate there," he said.

To a question on the shortcomings in the performance of women officers as Commanding Officers as revealed by a recent letter by a Corps Commander to the Eastern Army Commander, Gen. Dwivedi firstly noted that the letter should not have been leaked and an inquiry has been ordered. Women officers are doing "exceedingly well" and one kind of example cannot be taken as a yardstick. "Wherever I have seen, women officers have been very mature, considerate, kind... and up and above," he said.

To a query on the row over the 1971 painting, he described the new one as depicting India's civilisation connect and modern technology as also reaching out to the newer generations.

- ▶ उनके वक्तव्यों से उभरती हुई सैन्य गतिशीलता पर प्रकाश पड़ता है, विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और नियंत्रण रेखा (LoC) के साथ कई बिंदुओं पर चल रहे सीमा गतिरोध, मुठभेड़ों और सुरक्षा चिंताओं के बारे में।

### महत्वपूर्ण स्थान

- ▶ सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक): सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक संकरा भूमि मार्ग है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अपनी कथित भेद्यता के बावजूद, यह वास्तव में भारत का सबसे मजबूत रणनीतिक बिंदु है।

- डोकलाम: डोकलाम भूटान के पास एक त्रिकोणीय जंक्शन क्षेत्र है, जहाँ भारत, चीन और भूटान मिलते हैं। इस क्षेत्र में चीन द्वारा बुनियादी ढाँचे का निर्माण भारत के लिए चिंता का विषय रहा है, क्योंकि यह दोनों देशों को करीब लाता है।
- डेपसांग मैदान: डेपसांग मैदान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी के करीब स्थित है।
  - महत्वपूर्ण सब-सेक्टर नॉर्थ (SSN) में डेपसांग मैदान और दौलत बेग ओल्डी (DBO) शामिल हैं। वर्तमान में, डीबीओ में हवाई क्षेत्र 255 किलोमीटर लंबी दरबुक-श्योक-डीबीओ (डीएसडीबीओ) सड़क द्वारा पहुँचा जा सकता है।
  - डेपसांग, कराकोरम दर्रे के भी करीब है, जहाँ से रणनीतिक साल्टोरो रिज और सियाचिन ग्लेशियर दिखाई देता है, जो दुनिया का सबसे ऊँचा युद्धक्षेत्र है।
- डेपसांग मैदानी इलाकों का मुद्दा 2013 में शुरू हुआ था, जब चीन ने इस क्षेत्र में 18 किलोमीटर की घुसपैठ की थी।
- डेमचोक: डेमचोक पूर्वी लद्दाख के दक्षिणी भाग में है। डेमचोक में, समस्या मुख्य रूप से चारडिंग निंगलुंग नाला (सीएनएन) जंक्शन पर है।

### LAC क्या है?

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा है, जो लगभग 4,057 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह जम्मू और कश्मीर में भारतीय-नियंत्रित क्षेत्रों को अक्साई चिन के चीनी-अधिकृत क्षेत्र से अलग करती है।
- एलएसी लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित कई क्षेत्रों से होकर गुजरती है।
- ऐतिहासिक रूप से, LAC 1962 के भारत-चीन युद्ध से उभरा, जब दोनों देशों की सेनाएँ इस रेखा पर तैनात थीं।
- समय के साथ, यह 1993 और 1996 में किए गए समझौतों के माध्यम से एक मान्यता प्राप्त सीमा बन गई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई भी पक्ष इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
- हालाँकि, स्पष्ट सीमांकन की कमी के कारण, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच अक्सर मुठभेड़ होती रहती है।

### LOC क्या है?

- इसके विपरीत, नियंत्रण रेखा (LOC) भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य नियंत्रण रेखा है, जो लगभग 740 किलोमीटर तक फैली हुई है।
- यह जम्मू और कश्मीर को भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित भागों में विभाजित करती है, और इसे 1947 में पहले भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद स्थापित किया गया था।
- LAC के विपरीत, LOC अच्छी तरह से परिभाषित है, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएँ रेखा के साथ आमने-सामने तैनात हैं, जिससे अक्सर झड़पें होती हैं।

### मुख्य अंतर

- बफर जोन: LAC में आम तौर पर एक बफर जोन होता है जहाँ दोनों पक्ष सीधे संपर्क के बिना गश्त करते हैं, जबकि LOC की विशेषता लगातार सैन्य उपस्थिति और टकराव है।
- नियंत्रण की प्रकृति: एलएसी ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम है और इसमें स्पष्ट सीमांकन का अभाव है, जबकि एलओसी युद्धों और समझौतों के बाद स्थापित एक स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमा है।

असम के दीमा हसाओ जिले में हाल ही में घटित घटना, जहां एक रैट-होल खदान में बाढ़ आने के कारण कई श्रमिक फंस गए थे, इस अनियमित खनन प्रथा के जारी खतरों को उजागर करती है।



**In vain:** Efforts underway to rescue the labourers trapped inside an illegal rat-hole coal mine, in Dima Hasao district, Assam, on January 9, 2025. PTI

## Rat-hole mining: why the practice continues in spite of its hazards

Labourers mainly from Assam, Nepal, and adjoining Bangladesh risk the hazards of rat-hole mining – asphyxiation because of poor ventilation, collapse of mines due to lack of structural support, and flooding – to earn thrice or four times as much as working in farms or construction sites

**Rahul Karmakar**

On January 6, 2025, nine workers were trapped in a flooded coal mine in Assam's Dima Hasao district. Bodies of four of the workers have been recovered, and rescue work is still ongoing. In this article, dated November 29, 2023, Rahul Karmakar explains the dangers of rat-hole mining.

**The story so far:**  
A oral question from the Supreme Court to the Union government continues to remain unanswered even as rescue workers recover bodies of workers who died trapped in a flood rat-hole coal mine at Dima Hasao district in Assam. On January 11, 2019, the top court had asked whether rat-hole mines could possibly operate in the northeast hills without the "connivance" of officials. "Lives are lost due to illegal mining. What about the officials who allowed this to happen?" the court had asked the government.

**What is rat-hole mining?**  
Rat-hole mining, of two types, is so named as it involves digging tunnels 3-4 feet deep, barely allowing workers to crawl in and out. They have to squat while extracting coal with pickaxes. The side-cutting type of mining is usually done on hill slopes by following a coal seam – dark brown or black-banded coal deposited within layers of rock – visible from the outside. The second type called back-cutting entails digging a circular or

squarish pit at least 5 sq. metre in width up to a depth of 400 feet. Miners who drop down in makeshift cranes or using rope-and-bamboo ladders dig horizontally after finding the coal seam. The tunnels are dug in every direction from the edge of the pit, resembling the tentacles of an octopus. Some workers from Assam lost their lives in the coal mines of Meghalaya, dug using this crude method, before and after the National Green Tribunal (NGT) banned it in April 2014.

**Why is such mining banned?**

The government has little control over the land in Meghalaya, a Sixth Schedule State where the Coal Mines Nationalisation Act of 1973 does not apply. The landowners are thus also the owners of the minerals beneath. Coal mining boomed after Meghalaya attained statehood in January 1972. However, the terrain and expenses involved discouraged mine owners from employing advanced drilling machines. So, labourers mainly from Assam, Nepal, and adjoining Bangladesh risked the hazards of rat-hole mining – asphyxiation because of poor ventilation, collapse of mines due to lack of structural support, and flooding – to earn thrice or four times as much as working in farms or construction sites. Apart from issues of safety and health, unregulated mining led to land degradation, deforestation, and water with high concentrations of sulphates, iron, and toxic heavy metals,

low dissolved oxygen, and high biochemical oxygen demand. At least two rivers, Lukha and Myritdu, became too acidic to sustain aquatic life. These factors led to the NGT banning rat-hole mining in Meghalaya in 2014 while observing: "...there is umpteen number of cases where, by virtue of rat-hole mining, during the rainy season, water flooded into the mining areas resulting in the death of many..." Illegal mining and transportation of coal, as mentioned in the interim reports of a one-man committee appointed by the High Court of Meghalaya, has continued despite the ban and the loss of lives. At least 17 miners were drowned in an illegal mine in the East Jaintia Hills district's Ksan in December 2018 after water gushed in from a river.

**What led to the NGT ban?**

Environmentalists and human rights activists began flagging the hazards of rat-hole mining in Meghalaya two decades ago. The campaign intensified after Impulse, a Meghalaya-based NGO, began addressing the issue of human trafficking and child labour in such mines.

Three reports prepared by the NGO, first with the Nepal-based Esther Benjamin Trust in May 2010, the second with Aiké et Action in December 2010, and the last with Human Rights Now in July 2011, estimated that about 70,000 children mostly from Bangladesh and Nepal were employed in these mines

because they were the right size to work in them. The State's Department of Mining and Geology refuted the claim but, under pressure from the National Human Rights Commission, admitted in June 2013 that 222 children were employed in rat-hole mines, specifically in the East Jaintia Hills district. The NGT ban came a year later.

**What is the way forward?**

Unlike in Chhattisgarh and Jharkhand, coal seams in Meghalaya are very thin. This, miners say, makes rat-hole mining more economically viable than opencast mining.

The State has an estimated reserve of 576.48 million tonnes of low-ash, high-sulphur coal belonging to the Eocene age (33-56 million years ago). The stakes for a section of locals have been so high that the State government has been under pressure to facilitate the resumption of mining legally.

In May 2023, Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma said the Coal Ministry approved mining leases for four of the 17 prospective licence applicants. This would lead to the commencement of 'scientific' mining ensuring minimal environmental impact through sustainable and legally compliant extraction procedures. Anti-mining activists, who are assaulted by miners off and on, said that 'scientific' would eventually be a fancy tag in a State where profit has driven coal mining.

### रैट-होल माइनिंग क्या है?

- ➔ रैट-होल माइनिंग कोयला निकालने की एक विधि है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर पूर्वोत्तर भारत, खासकर मेघालय में संकीर्ण, क्षैतिज कोयला सीमों में किया जाता है।

- इसमें संकीर्ण गड्ढे या सुरंग खोदना शामिल है, जिन्हें "रैट होल" कहा जाता है, जो एक व्यक्ति के प्रवेश के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। श्रमिक रस्सियों या बांस की सीढ़ियों का उपयोग करके इन गड्ढों में उतरते हैं और कुल्हाड़ी और फावड़े जैसे बुनियादी उपकरणों से मैनुअल रूप से कोयला निकालते हैं।

### रैट-होल माइनिंग के दो मुख्य प्रकार हैं:

- साइड-कटिंग: पहाड़ी ढलानों पर संकीर्ण सुरंगें तब तक खोदी जाती हैं जब तक कि कोयला सीमा न मिल जाए, जो आमतौर पर 2 मीटर से कम मोटी होती है।
- बॉक्स-कटिंग: एक आयताकार उद्घाटन बनाया जाता है, और कोयला निकालने के लिए क्षैतिज सुरंगों के साथ 400 फीट गहरा एक ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदा जाता है।
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 2014 में रैट-होल माइनिंग पर इसके गंभीर पर्यावरणीय और सुरक्षा जोखिमों के कारण प्रतिबंध लगा दिया था। 2015 में घातक दुर्घटनाओं की रिपोर्ट के बाद प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था, खासकर बरसात के मौसम में जब खदानों में बाढ़ आने का खतरा होता है।
- प्रतिबंध के बावजूद, अवैध रैट-होल खनन जारी है, खासकर मेघालय जैसे क्षेत्रों में, स्थानीय समुदायों के लिए व्यवहार्य वैकल्पिक आजीविका की कमी के कारण।

### सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:

- सुरक्षा जोखिम: उचित वेंटिलेशन, संरचनात्मक समर्थन और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण खनन प्रक्रिया खतरनाक है। कई दुर्घटनाएँ और मौतें हुई हैं, खासकर जब सुरंगें ढह जाती हैं या पानी भर जाता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: रैट-होल खनन से भूमि क्षरण, वनों की कटाई और जल प्रदूषण होता है, क्योंकि यह प्रक्रिया उचित अपशिष्ट प्रबंधन के बिना परिदृश्य के बड़े क्षेत्रों को परेशान करती है।



**In News : Mission Mausam**

प्रधानमंत्री भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान 'मिशन मौसम' का शुभारंभ करेंगे।



**मिशन मौसम के बारे में:**

- इसका उद्देश्य भारत के मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान, अनुसंधान और सेवाओं को बढ़ावा देना और भारत को 'मौसम के लिए तैयार और जलवायु-स्मार्ट' राष्ट्र बनाना है।
- दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाला यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम-अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- यह पूर्वानुमान सटीकता को बढ़ाएगा, लगभग वास्तविक समय के स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा और मौसम प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के विकास पर शोध करेगा।
- मिशन का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को विकसित करके, उच्च-रिज़ॉल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटरों को लागू करके इसे प्राप्त करना है।

- इन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर, कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वानुमान की स्थानिक और लौकिक सटीकता में सुधार करने और जलवायु परिवर्तन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में मदद करने के लिए डेटा संग्रह और विश्लेषण को परिष्कृत करना है।
- यह मौसम और जलवायु प्रक्रियाओं की समझ को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, और वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करेगा जो लंबे समय में मौसम प्रबंधन और हस्तक्षेप की रणनीति बनाने में मदद करेगा।
- यह चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों और अंतिम-मील उपयोगकर्ताओं सहित हितधारकों को बेहतर ढंग से लैस करने में मदद करेगा।

### भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के बारे में:

- IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
- मौसम विज्ञान के महानिदेशक IMD के प्रमुख हैं।
- 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें से प्रत्येक एक उप महानिदेशक के अधीन है, जिसका मुख्यालय मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर और गुवाहाटी में है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- वर्तमान में, IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन है।
- यह मौसम संबंधी अवलोकन करता है और कृषि, शिपिंग, विमानन, अपतटीय तेल अन्वेषण आदि जैसी मौसम-संवेदनशील गतिविधियों के लिए वर्तमान और पूर्वानुमानित मौसम संबंधी जानकारी और आँकड़े प्रदान करता है।

# Transforming 'men'talities, redefining masculinity

As another International Day for the Elimination of Violence Against Women passes by (November 25), we face a stark truth: despite decades of advocacy, nearly one in three women worldwide has endured violence at the hands of men. While men are often the perpetrators, they can also be key agents of change. Addressing violence against women requires addressing men's roles and questioning traditional notions of masculinities based on strength, aggression and control. These notions need to be replaced by a culture where equality, empathy, and non-violence define alternative notions of manhood.

Violence against women can be seen, somewhat paradoxically, as a quintessential "men's issue" – a societal issue that demands the active engagement of men. From early childhood, boys are influenced by norms that tell them strength is dominance, that emotions are a weakness, and that asserting control is the way to protect their status. These deeply entrenched ideas not only harm women but also limit men's lives and their relationships, trapping them in cycles of suppressed emotions and aggressive behaviours. Recognising and reshaping these norms is essential for creating healthier relationships and a safer world.

The subject of men and masculinities has become a prominent focus within the development sector. Over the past two decades, academic research and grass-root efforts have revealed the importance of engaging with men, highlighted strategies that work, and shown how men are increasingly stepping out to challenge traditional gender norms. This growing shift reflects a recognition among men of their role in advancing gender equality.

## An India report

UNESCO's Transforming MENTalities initiative has aimed to shift the way men engage with gender issues – not just as allies but as active participants in social transformation. This initiative challenges rigid and stereotyped ideas of masculinity and



**Tim Curtis**

Director, UNESCO  
South Asia Regional  
Office, part of Team  
UN in India



**Ravi Verma**

Executive Director,  
International Center  
for Research on  
Women (ICRW) Asia

A UNESCO initiative with the goal of changing the way men engage with gender issues is making progress

fosters positive, supportive roles for men, engaging them as champions for gender equality. As we inch closer to Agenda 2030 – working to create an inclusive and equal world – UNESCO, in collaboration with the International Center for Research on Women (ICRW), is proud to present the report, "Engaging Men and Boys: A Report on Pathways to Gender Equality in India". This report documents 10 pioneering programmes across India that engage men and boys to address gender inequality.

## Some of the interventions

Through impactful initiatives, these programmes encourage critical dialogues that are aimed at questioning traditional gender norms, reshaping concepts of masculinity, and fostering inclusive attitudes. By emphasising education, open discussions, and community-driven actions, these programmes empower participants to become advocates for gender equity within their household and within communities and institutions they are part of.

For example, 'Mardon Wali Baat (A man's thing)', an initiative by The YP Foundation, uses storytelling and social media to foster conversations around positive masculinities with young men on campuses and in communities. This intervention helps young men critically examine the limiting narratives they have grown up with, empowering them to embrace values of respect and equality. Similarly, Gender Equity Movement in Schools (GEMS), a collaboration between the ICRW and the Department of Education in the State of Rajasthan, uses interactive classroom activities to help adolescent boys see the harm in toxic masculinity and adopt more equitable gender attitudes. In one session, a boy reflected, "I used to think boys should only do outdoor chores. Now, I believe we should work alongside women at home." These moments of transformation create ripple effects that can reshape entire communities.

Initiatives such as 'Dekh Rekh (caring for each other)' and 'Hamari Shaadi (our marriage)

encourage men's active participation in family nutrition and planning, tackling gender bias through small, everyday actions. These interventions prove that when men and boys are invited to engage with gender equality as a part of their lives, rather than as an abstract idea, change becomes possible.

## The defining role of public figures

Change also becomes possible when men and boys have positive role models demonstrating equitable behaviours. These initiatives underscore the importance of role models who actively participate in household and care-giving responsibilities, reject violence as a solution, practise empathy, and embrace vulnerability. Public figures, in particular, can help normalise gender equality. For instance, a well-known Indian cricketer recently sparked a national conversation on shared parenting and responsibility by publicly committing to paternity leave. Actions such as these highlight how equitable relationships are rooted in care, respect, and partnership, redefining what it means to "be a man" in ways that uplift both individuals and communities.

The path to true equality is long, and the active participation of men is crucial in this journey. Beyond rejecting violence, men can challenge the stereotypes and cultural norms that perpetuate it. They must see themselves as essential contributors to change, helping dismantle toxic ideas of manhood. This requires a willingness to question the privileges that patriarchy grants the world and to explore ways to address the pressures and expectations that accompany these privileges. By reflecting on and reshaping their roles, men can play a transformative part in building a more equitable society for all.

In the new year, let us celebrate those men and boys who are "Transforming MEN'talities" and championing equality. Together, by redefining masculinity, we can create a world where every individual, regardless of gender, is free from violence and empowered to thrive.

**GS Paper 01 :** भारतीय समाज: महिलाओं से संबंधित मुद्दे

**UPSC Mains Practice Question:** महिलाओं के खिलाफ हिंसा लैंगिक समानता और सतत विकास को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। इस मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से वैश्विक और राष्ट्रीय पहलों पर चर्चा करें, और उनकी प्रभावशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में प्रयासों को मजबूत करने के उपाय सुझाएँ। (250 Words /15 marks)

## संदर्भ:

- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (25 नवंबर) लिंग आधारित हिंसा के लगातार वैश्विक मुद्दे की एक गंभीर याद दिलाता है।
- दशकों की वकालत के बावजूद, दुनिया भर में लगभग तीन में से एक महिला पुरुषों के हाथों हिंसा का शिकार हुई है।
- यह चौंकाने वाला आँकड़ा पुरुषों को न केवल अपराधी के रूप में बल्कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का मुकाबला करने में बदलाव के प्रमुख एजेंट के रूप में शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

## महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मूल कारण और पुरुषों को शामिल करने में प्रगति

### प्रारंभिक समाजीकरण और हानिकारक अपेक्षाएँ

- कई समाजों में, लड़कों को ऐसे संदेशों के साथ पाला जाता है जो मर्दानगी को अधिकार और नियंत्रण के बराबर मानते हैं।
- 'लड़के रोते नहीं' और 'मर्द बनें' जैसे आम वाक्यांश भावनात्मक अभिव्यक्ति को दबाते हैं, जिससे लड़कों को अपनी भावनाओं को आंतरिक रूप से व्यक्त करने पर मजबूर होना पड़ता है।
- यह भावनात्मक दमन अक्सर निराशा, आक्रामकता या भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी के रूप में प्रकट होता है, जो उनके रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकता है।
- लड़कों को शक्ति को प्रभुत्व से जोड़ना भी सिखाया जाता है, जिससे यह धारणा बनती है कि उन्हें अपनी मर्दानगी की पुष्टि करने के लिए दूसरों, अक्सर महिलाओं पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए।
- ये सामाजिक संदेश परिवारों में लैंगिक अपेक्षाओं द्वारा पुष्ट होते हैं।
- उदाहरण के लिए, लड़के देख सकते हैं कि घर के निर्णय लेना और बाहरी गतिविधियाँ पुरुषों के लिए आरक्षित हैं, जबकि देखभाल और घरेलू काम महिलाओं की ज़िम्मेदारियाँ मानी जाती हैं।

### विषाक्त मर्दानगी

- विषाक्त मर्दानगी, पारंपरिक पुरुष भूमिकाओं से जुड़े हानिकारक व्यवहार और दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, समस्या को और भी जटिल बनाता है।
- यह आक्रामकता, प्रतिस्पर्धा और प्रभुत्व पर जोर देता है, जिसे अक्सर हानिकारक तरीकों से व्यक्त किया जाता है।
- इन मानदंडों से प्रभावित पुरुष नियंत्रण स्थापित करने या संघर्षों को हल करने के लिए हिंसा का सहारा ले सकते हैं, खासकर उन स्थितियों में जहाँ उनके अधिकार को चुनौती दी जाती है।
- यह घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा के अन्य रूपों में एक महत्वपूर्ण कारक है।
- विषाक्त मर्दानगी पुरुषों को भी प्रभावित करती है, उन्हें भावनात्मक अलगाव और विनाशकारी व्यवहार के चक्र में फँसाती है।
- भेद्यता को व्यक्त करने में असमर्थता चिंता, अवसाद और मादक द्रव्यों के सेवन सहित खराब मानसिक स्वास्थ्य परिणामों को जन्म दे सकती है।

## मीडिया और सांस्कृतिक आख्यानो की भूमिका

- फिल्में, विज्ञापन और लोकप्रिय संस्कृति अक्सर पुरुषों को आक्रामक रक्षक या उदासीन प्रदाता के रूप में चित्रित करती हैं, जबकि महिलाओं को निष्क्रिय देखभाल करने वाले या पीड़ित के रूप में दर्शाया जाता है।
- इस तरह के चित्रण द्विआधारी लिंग भूमिकाओं को मजबूत करते हैं और इन मानदंडों से विचलन को हतोत्साहित करते हैं।
- इन आख्यानो को सुनने वाले लड़के अक्सर इन रूढ़िवादी आदर्शों को अपनाने की आकांक्षा रखते हैं, जिससे विषाक्त मर्दानगी और भी मजबूत होती है।
- कुछ संस्कृतियों में, धार्मिक या पारंपरिक मान्यताएँ हानिकारक लिंग मानदंडों को भी मजबूत कर सकती हैं।

## पुरुषों को शामिल करने में प्रगति

- हाल के वर्षों में, विकास क्षेत्र ने लैंगिक समानता प्राप्त करने में पुरुषों और पुरुषत्व की भूमिका पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।
- शैक्षणिक अनुसंधान और जमीनी स्तर के प्रयासों ने पारंपरिक लिंग मानदंडों को चुनौती देने में पुरुषों को शामिल करने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर प्रकाश डाला है।
- ये पहल पुरुषों के बीच लैंगिक समानता में योगदान करने की बढ़ती इच्छा को दर्शाती हैं, निष्क्रिय सहयोगियों के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में।

## केस स्टडी: लैंगिक समानता के प्रति भारत का दृष्टिकोण

- **यूनेस्को की मानसिकता में बदलाव की पहल**
  - यूनेस्को की मानसिकता में बदलाव की पहल पुरुषों और लड़कों को शामिल करके लैंगिक असमानता के मूल कारणों को दूर करने के लिए एक व्यापक प्रयास के रूप में सामने आई है।
  - लैंगिक समानता की लड़ाई में उन्हें केवल सहयोगी के रूप में मानने के बजाय, यह पहल उन्हें सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भागीदार के रूप में पेश करती है।
  - मर्दानगी के कठोर और हानिकारक विचारों को खत्म करके, यह पुरुषों को अपने परिवारों और समुदायों के भीतर सकारात्मक, सहायक भूमिकाएँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  - इस पहल के हिस्से के रूप में, यूनेस्को ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन (ICRW) के साथ मिलकर एंगेजिंग मेन एंड बॉयज़: ए रिपोर्ट ऑन पाथवेज़ टू जेंडर इकैलिटी इन इंडिया नामक रिपोर्ट तैयार की।
  - यह रिपोर्ट उन अग्रणी कार्यक्रमों का दस्तावेजीकरण करती है, जिन्होंने लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर करने, समान दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और स्थायी परिवर्तन लाने में पुरुषों और लड़कों को सफलतापूर्वक शामिल किया है।

## अग्रणी कार्यक्रम और उनका प्रभाव

### ➤ मर्दों वाली बात (पुरुषों की बात)

- वाई.पी. फाउंडेशन द्वारा संचालित, यह पहल कॉलेज परिसरों और समुदायों में युवा पुरुषों को जोड़ने के लिए कहानी कहने और सोशल मीडिया का उपयोग करती है।
- यह प्रतिभागियों को मर्दानगी के इर्द-गिर्द सामाजिक आख्यानो की आलोचनात्मक जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि ताकत को प्रभुत्व के साथ जोड़ना, और सम्मान, समानता और भावनात्मक खुलेपन के मूल्यों को अपनाना।
- सकारात्मक मर्दानगी पर बातचीत करके, यह कार्यक्रम युवा पुरुषों को उनके व्यक्तिगत जीवन और समुदायों में रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए तैयार करता है।

### ➤ स्कूलों में लैंगिक समानता आंदोलन (जी.ई.एम.एस.)

- आई.सी.आर.डब्ल्यू और राजस्थान शिक्षा विभाग के बीच सहयोग से, जी.ई.एम.एस. इंटरैक्टिव कक्षा गतिविधियों के माध्यम से विषाक्त मर्दानगी को संबोधित करने के लिए किशोरों के साथ काम करता है।
- महत्वपूर्ण चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करके, कार्यक्रम लड़कों को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं से होने वाले नुकसान को समझने में मदद करता है और उन्हें समान दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- एक परिवर्तनकारी क्षण तब आया जब एक लड़के ने सोचा, "मैं सोचता था कि लड़कों को केवल बाहरी काम ही करने चाहिए। अब, मेरा मानना है कि हमें घर पर महिलाओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए।"
- इन अंतर्दृष्टियों का एक लहर जैसा प्रभाव है, जो न केवल लड़कों को बल्कि उनके परिवारों और साथियों को भी प्रभावित करता है।

### ➤ देख रेख (एक दूसरे की देखभाल) और हमारी शादी (हमारी शादी)

- ये कार्यक्रम पुरुषों को घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारियों, जैसे परिवार नियोजन और पोषण में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- पुरुषों को पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा वर्चस्व वाले घरेलू क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करके, ये पहल गहरी जड़ें जमाए हुए लिंग पूर्वाग्रहों को चुनौती देती हैं और रोजमर्रा की गतिविधियों के माध्यम से समानता को बढ़ावा देती हैं।

## आगे का रास्ता

- मूल कारणों को संबोधित करने के लिए मानदंडों को फिर से आकार देना
- रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा आवश्यक है, लड़कों को सिखाएं कि भेद्यता, सहानुभूति और समानता ताकत हैं, कमज़ोरियाँ नहीं।
- परिवारों, स्कूलों और समुदायों को मर्दानगी की वैकल्पिक, स्वस्थ परिभाषाओं को मॉडल बनाना और बढ़ावा देना चाहिए।
- सार्वजनिक अभियान, मीडिया प्रतिनिधित्व और सकारात्मक रोल मॉडल यह दिखाकर इन संदेशों को और मजबूत कर सकते हैं कि मर्दानगी भावनात्मक खुलेपन, साझेदारी और महिलाओं के प्रति सम्मान के साथ सह-अस्तित्व में रह सकती है।

## समुदाय-संचालित दृष्टिकोण

- इन कार्यक्रमों की सफलता उनके समुदाय-संचालित दृष्टिकोण में निहित है।

## Daily News Analysis

- स्थानीय संदर्भों और सांस्कृतिक बारीकियों को एकीकृत करके, ये पहल प्रतिभागियों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं और लैंगिक समानता प्रयासों के जमीनी स्तर पर स्वामित्व विकसित करती हैं।
- उदाहरण के लिए, जटिल विचारों को सुलभ और संबंधित बनाने के लिए इंटरैक्टिव सत्र, कहानी सुनाना और भूमिका निभाने वाली गतिविधियों का उपयोग किया जाता है।
- इसके अलावा, पुरुषों और लड़कों को उनके अपने सामाजिक परिवेश में शामिल करना सुनिश्चित करता है कि परिवर्तन बाहर से थोपा नहीं जाता है बल्कि स्वाभाविक रूप से उभरता है, जिससे यह अधिक टिकाऊ बनता है।

### निष्कर्ष

- जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम उन पुरुषों और लड़कों का जश्न मनाएं जो पारंपरिक मर्दानगी को चुनौती दे रहे हैं और समानता की वकालत कर रहे हैं।
- 'पुरुष होने' का क्या अर्थ है, इसे फिर से परिभाषित करके, हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ हर कोई, लिंग की परवाह किए बिना, हिंसा से मुक्त हो और फलने-फूलने के लिए सशक्त हो।
- शिक्षा, वकालत और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त किया जा सकता है तथा हम अधिक न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाज का निर्माण कर सकते हैं।